International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 12, December 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

वैश्विकरण एवं पर्यावरण सम्मेलनःभारत पर बढ़ता दबाब

संजय कुमार सिंह
शोधार्थी
राजनीति विज्ञान विभाग, तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

वैश्विक पटल पर पर्यावरण एवं इससे जुड़े सभी मुद्दे आज का ज्वलंत विषय है। खासकर इस स्थिति में जब मानव द्वारा प्रगति और विकास के नाम पर अंधाधुन प्रकृति का दोहन हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के प्राकृतिक घटनाओं, विपदाओं, प्रदुषणों आदि का सामना करना पड़ रहा है। भारत भी पीड़ित देश है। भारत की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधता, विकासशील से विकसित देश बनने की होड़, गरीबी, अशिक्षा, वन–जंगलों पर आश्रित वनवासियों की बड़ी तादात से पर्यारण संरक्षण चुनौतीपूर्ण हो गया है। [1] औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप उत्पादन की प्रक्रिया तेज हुइ। 19 वीं शताब्दी के अंत में यह स्प''ट हो गया कि यह प्रक्रिया प्र्यावरण को व्यापक क्षति पहुँचा रही है। [2] सम्पूर्ण विश्व में पर्यावणीय संकट गहरा गया है।

वैश्विक पर्यावरण घटनाएँ:– असामान्य जनवृद्धि और उनके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूर्खतापूर्ण उपयोंग से विरासत से मिलें संसाधनों में कमी आने लगी। आवास हेतु घने वनों की अनवरत कटाई से वन क्षेत्र कम होते गए। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगा। विकासशील और विकसित देशों की अधिक संसाधन जुटाने की होड़ से औद्योगिकरण में वृद्धि हुई तो अनेक प्रकार की भयावह घटनाएँ घटने लगी, जिनसे बच पाना कठिन था। पिछले 50 वर्षों में घटी घटनाओं का अवलोकन कर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

1. सन् 1940 में लॉस–ऐजिंल्स शहर (USA) में एक शाम पूरा शहर धुएँ के बादलों से ढ़क गया। लोगों में पहले थोड़ी बेचैनी, फिर घबराहट और उसके बाद सॉस लेने में कठनाई हुई। फिर अप्रत्याशित धुएँ के आवरण ने उस रात कई हजार लोगों की जाने ली।
2. सन् 1952 में लंदन (UK) में "London Episode of SMOG" अथवा भस्मोग घटना'' के नाम से बहुचर्चित घटना घटी। एक शाम उद्योगों और कारखानों से निकले धुएँ तथा वायुमंडलीय आदंता से कुहरे की परत पूरे लंदन शहर को ढ़ँक लिया। घबराहट, बेचैनी तथा श्वास अवरोध ने लगभग 5000 लोगों की जीवन लीलाएँ समाप्त की।
3- जापान की मिनीमाटा खाड़ी के तटीय भाग में बड़े–बड़े कारखानें लगे हैं। एक कारखाना से उत्सर्जित जहरीली 'एल्काइल मरकरी कम्पाउंड' भारी मात्रा में खाड़ी के पानी में मिल गई। अनेक जलीय जीव मर गए। खाड़ी की मछलियों और जानवरों को भोज्य रूप में ग्रहण करने से लोगों में एक खास प्रकार का चकत्ते वाला रोग हुआ, जिसे भमिनीमाटाभ नाम दिया गया। लकवा, हाथ–पैर की जकरन, मस्तिष्क विकृति, बहरापन, दृष्टिदोष आदि रोगों से ग्रसित हुए और लोग मौत के शिकार हुए। [3]
4. भोपाल गैस दुर्धटना भी इसी की एक कड़ी है जिसमें लाखों लोग प्रभावित हुए, हजारों मरे। इस घटना का कारण भमिथाइल आइसोसाइनाईभ का रिसाव था।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 12, December 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

इसके अतिरिक्त भी विश्व भर में अनेक पर्यावरणिक छोटी–बड़ी घटनाएँ घटती रही है और लोगों की जाने जाती रही है।

वैश्विक पर्यावरणिक प्रभाव और पर्यावरण संरक्षण की नैदानिक नीतियाँः–

वैश्विकरण और राष्ट्र–राज्यों के बीच परस्पर निर्भरता सभी पर्यावरण समस्याओं को एक अंतराष्ट्रीय आयाम प्रदान करते हैं। औद्योगिकरण महत्वपूर्ण रूप से पर्यावरण को प्रभावित करते हैं।[4] कुछ समस्याएँ व्यापक रूप से सभी देशों की बन गई है। ग्रीनहाउस प्रभाव, आजोन परत का विघटन तेजाबी वर्षा, रेगिस्तानी क्षेत्र में वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या के दुष्प्रभाव, ध्वनि प्रदूषण आदि को उनमें रखा गया जा सकता है। सक्षम देश इन समस्याओं के निदान व उनको दूर करने के उपाय अपनी कार्य योजनाओं में सम्मिलित किये है। कार्य का विषय एक होते हुए भी उनकी कार्यशैली अलग–अलग रही। विभिन्न देशों की पर्यावरण सुरक्षा एवं सुधार के क्षेत्र की प्राथमिकताएँ भिन्न–भिन्न है, जैसेः–

आस्ट्रेलिया (Australia):- (क) रेगिस्तान की वृद्धि को रोकना, (ख) भूमि प्रबंध (ग) पानी की उचित प्रबंध व्यवस्था (घ) उर्जा की बचत के उपाय आदि।

ब्रिटेन (Britain):- (क) वन एवं वन्यजीव संरक्षण, (ख) भूमि का पुनः चक्रण (ग) जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण (घ) समुद्री प्रदूषण (ड0) विकिरण से बचाव, (च) अवशि"ट निस्तारण (छ) राष्टोय उद्यानों का रख–रखाव (ज) ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण आदि।

कनाडा (Canada):- (क) 2000 तक CFC से मुक्ति (ख) So_2 उत्सर्जन पर नियंत्रण (ग) ग्रीन हाउस प्रभाव की रोकथाम (घ) खतरनाक अवशिष्टों से बचाव (ड0) पर्यावरण अनुकूल उत्पाद आदि।

चीन (China):- (क) प्रकृति संरक्षण (ख) पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम (ग) औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण (घ) जैव विविधता की सुरक्षा आदि।

फ्रांस (France):- (क) पृथ्वी का भूकंपों से बचाव (ख) सधन वनीकरण (ग) समुद्र स्वच्छता (घ) ओजोन परत की सुरक्षा (ड0) ग्रीन हॉउस प्रभाव की रोकथाम (च) शारीरिक स्वास्थ्य आदि।

नार्वे (Norway):- (क) प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा एवं संरक्षण (ख) तेल प्रदूषण (ग) ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम आदि।

स्वीडन (Sweeden):- (क) तेजाबी वर्षा की रोकथाम (ख) समुद्री झील व अन्य जल भंडारों को जलकुंभी से बचाव (ग) धातु प्रदूषण (घ) अवशिष्ट एवं खतरनाक अवशेषों की बुद्धिमत्तापूर्ण निस्तारण आदि।

वेनेजुएला (Venezuela):- (क) अपशिष्ट जल को उपचार (ख) समुद्री पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखना (ग) समुद्री पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखना (घ) पर्यावरण शिक्षा का प्रावधान आदि।[5]

कुछ प्रमुख देशों के पर्यावरण संबंधी समस्याओं एवं संरक्षणों के उपाय, पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण लगभग एक जैसा ही है। विश्व के सभी देशों के बीच रणनीतिक भेद एवं प्राथमिकताओं की वजह भौगोलिक परिस्थितियों की भिन्नता है। स्थितिजन्य सामानता की स्थिति में पर्यावरण संरक्षण नीति एक समान होनी चाहिए। लेकिन ऐसी बात नही है। आवश्यकता इस बात की है कि पर्यावरण संरक्षण एवं सवर्द्धन हेतु समान परिस्थिति वाले सभी देशों की रणनीति एक जैसी और योजनाबद्ध हो। विकसित तकनीक एवं 'ाोध वैश्विक साझेदारी पर आधारित हो। साथ ही साथ तालमेल भी हो।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 12, December 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

पर्यावरण सम्मेलन

सांस्कृतिक और आर्थिक मानव के वैज्ञानिक मानव बनने तक का सफर सम्पूर्ण जीव–जगत को विनाश के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया है। सांस्कृतिक मानव का विकासोन्मुख कार्य पर्यावरण को काफी क्षति पहुँचाई। विज्ञान का ज्ञान भावी पर्यावरणिक दुष्प्रभाव, दुष्परिणाम और समस्या की ओर ध्यान दिलाया। भावी वैश्विक चिंता के प्रति समय रहते सजग होने के लिए चेताया। इसका परिणाम 20वीं शताब्दी के सत्तर के दशक में वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन के रूप में सामने आया। 20वीं शताब्दी के सभी सम्मेलनों का महत्व आधारिक है। परिणाम सकारात्मक पर सम्पूण चिंता निवारक नहीं रहा। 21वीं शताब्दी के प्रथम दो दशकों के पर्यावरणिक सम्मेलन दीर्घकालीन लक्ष्यात्मक रहा है, जिसमें पर्यावरण सुधार हेतु कई कोष की स्थापना के साथ–साथ मसौदे प्रस्तुत किए गए। कई परिकल्पनाएँ अस्तित्व में आई। लगभग 5 दशकों में आयोजित पर्यावरण सम्मेलनों का क्रमिक अध्ययन एवं परीक्षण निम्न है:–

स्टॉकहोम सम्मेलन, 1972:– पर्यावरण की सुरक्षा हेतु वैश्विक स्तर पर प्रथम प्रयास 5जून 1972 को किया गया था। U.N.O के तत्वाधान में इस वर्ष स्टॉकहोम में एक सम्मेलन आयोजित किया गया और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) आरंभ हुआ। इसी सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इस सम्मेलन को 'स्टॉकहोम समझौता' या 'प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन' के नाम से जाना जाता है।[6]

साइटस (CITES) (Conservation on international Trade in Endangered species):- 1973 में वाशिंगठटन सम्मेलन में ही इस पर सहमती बन गयी थी। परन्तु इसे 1976 से लागू किया गया। यह विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता था। यह समझौत जीव तथा उनके अंगो आदि के अन्तराष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करता है।

हलिंसकी सम्मेलन, 1974:– सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा के उद्येश्य से 1974 में हैलिंसकी सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

लंदन सम्मेलन, 1987:– समुद्र की स्वच्छता को बनाये रखने के उद्येश्य से लंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में समुद्र में कचरे के निस्तारण का प्रतिशोघ किया था। वियना सम्मेलन, 1985:– ओजोन परत के संरक्षण एवं बचाव हेतु आस्ट्रिया के वियना शहर में एक सम्मेलन किया गया था। जो ओजोन क्षरण पदार्थो के अत्सर्जन पर सम्पन्न प्रथम सार्थक प्रयास था।

मांट्रियल सम्मेलन, 1987:– ओजोन परत को क्षीण करने वाले उत्तदायी कारक क्लोरोफ्लोरो कार्बन, (CFC) मिथाइल ब्रोमाइड (HCFC) आदि पदार्थो के उत्सर्जन को रोककर उसको संरक्षित करने के लिए 16 सितम्बर ,1987 को यह समझौता हुआ। यह समझौता 1 जनवरी 1989 में प्रभावी हो गया। इसके बाद पहली बैठक मई 1989 में हेलिंसकी में हुई, जिसमें 16 सितम्बर को ''अन्तराष्ट्रीय ओजोन दिवस'' मनाने का निर्णय लिया गया।

पृथ्वी शिखर सम्मेलन, 1992:– स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगाठ मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ब्राजील के रियो–डी–जेनेरा शहर में 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया। इसे ''अर्थ समिट'' (Earth Summit) और 'प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन' भी कहा जाता है। इस सम्मेलन में सम्मिलित देशों ने 'टिकाउ विकास' के लिए व्यापक कार्य योजना ''एजेंडा 21'' स्वीकृत किया तथा जलवायु परिवर्तन

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 12, December 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

पर 'यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेंट चेंज' (UNFCCC) की स्थापना की गई। सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि विश्व के देश पृथ्वी के वायुमंडल के स्वास्थ्य और अखंडता को सुरक्षित और पुनः स्थापित करने के लिए विश्वव्यापी साझेदारी की भावना से सहयागे करेंगे। इस सम्मेलन में 'वैश्विक सुरक्षा कोष' बनाया, जो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने, जैव विविधता, जल संरक्षण एवं अन्तराष्ट्रीय संसाधनों के दोहन पर नियंत्रण मेंसहयोग देगा।

क्योटो प्रोटोकॉल 1997 (पृथ्वी + 5 सम्मेलन) :— ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में अनियंत्रित वृद्धि को रोकने के उद्धेश्य से यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। दिसम्बर 1997,को हुए UNFCCC के तीसर सम्मेलन अर्थात COP के तीसरे सत्र में क्योटो प्रोटोकॉल स्वीकार किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी, 2005 को पूर्ण रूप से लागू किया गया।

जोहान्सवर्ग सम्मेलन, 2002:— इसे रियो+10 और पृथ्वी+10 सम्मेलन भी कहा जाता है। इस सम्मेलन में सतत् विकास पर विशेष बल दिया गया तथा 'विश्व एकजुटता कोष' की स्थापना पर सहमति बनी थी।

मांट्रियल सम्मेलन–II (UNFFCC) 2005:— इस सम्मेलन में विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर 1990 के स्तर तक लाने का निर्णय लिया गया।

नुसा दुआ सम्मेलन, 2007:— इसे 'बाली रोड मैप' भी कहा जाता है। इस सम्मेलन में ग्रीन हाउस गैसों के उर्त्सजन की दर को वर्ष 2050 तक वर्ष 2000 तक के स्तर पर लाने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था।

कोपेहेगन सम्मेलन, 2009:— विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा वर्ष 2020 तक ग्रीन हाउस गैस के उर्त्सजन में भारी कटौती का प्रावधान इस सम्मेलन में किया गया था। 'कम कार्बन अर्थव्यवस्था' जैसी परिकल्पना भी प्रतिस्थापित की गई थी।

कानकुन सम्मेलन , 2010:— इस सम्मेलन में 'हरित जलवायु कोष' को स्थापित करने का निर्णय लिया गया था।

डरबन सम्मेलन (COP-17), 2011:— इस सम्मेलन में कानकुन सम्मेलन 2010 के निर्णयों के अनुरूप 'हरित जलवायु कोष' स्थापित किया गया।

दोहा सम्मेलन (COP-18), 2012:— पृथ्वी सम्मेलन के दो दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र का सतत् विकास सम्मेलन जिसमें ''द फ्यूचर वी वांट'' मसौदा प्रस्तुत किया। 'हरित व्यवस्था' पर भी बल दिया गया। इसे ''पृथ्वी–20 सम्मेलन'' भी कहा जाता है।

रियो+20 सम्मेलन, 2012:— पृथ्वी सम्मेलन के दो दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र का 'सतत् विकास सम्मेलन' जिसमें '' द फ्यूचर वी वांट'' मसौदा प्रस्तुत किया। हरित व्यवस्था पर भी बल दिया गया। इसे ''पृथ्वी–20 सम्मेलन'' भी कहा जाता है।

वारसा सम्मेलन (COP-19), 2013:— पौलेंड की राजधिानी वारसा में सम्पन्न सम्मेलन में ''ग्रीन क्लाइमेंट फंड'' बनाने की सहमति बनी थी।

लामा सम्मेलन (COP-20), 2014:— इस सम्मेलन में वर्ष 2070 तक ग्रीन हाउस गौसों के उत्सर्जन को समाप्त करने के लिए विश्व के देशों की प्रतिबद्धताओं को स्वीकारा गया।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 12, December 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

पेरिस सम्मेलन (COP-21), 2015:— इस संधि मे सभी देशों के लिए कार्बन उत्सर्जन की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई। कानूनी रूप देकर इसे बाध्यकारी बनाया गया।

बाब इधली सम्मेलन, मोरक्कों (COP-22), 2016:— इस सम्मेलन में हमारी जलवायु और सतत् विकास के लिए मराकेश कार्यवाही की उद्घोषणा की गई।

वॉन सम्मेलन, जर्मनी (COP-23), 2017:— इसमें 'फिजी मोमेंटम फार इम्पलीमेंटेशन' प्रस्तुत किया गया।

इन अन्तराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों के कार्यक्रमों, मसौदों आदि को कार्य रूप देने के लिए अर्थ स्केन, FAO, IAEA, IEEP, IUCN, UNFP, UNEP, UNESCO, UNIDO, WHO, WWF जैसे अन्तराष्ट्रीय अभिकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

वैश्विकरण एंव पर्यावरण सम्मेलन का भारत पर प्रभाव के सदभ में परीक्षण करने की आवश्यकता है। दुनियॉ की आबादी का बड़ा हिस्सा भारत में निवास करती है। कुछ मुद्दे ऐसे है जो वैश्विक अंतःसंबंधो से निर्धारित और प्रभावित होते है। मुद्दों की श्रृंखला की एक कड़ी पर्यावरण भी है। पर्यावरण किसी एक–दो देश का मामला न होकर वैश्विक मुद्दा बन गया है, इसलिए विश्व के अनेक देश अपने –अपने स्तर से इस क्षेत्र में भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा है। विश्व स्तर पर चल रही चर्चाओं के अनुरूप भारत में भी पर्यावरण में आयी विकृति से होने वाली किसी अनहोनी पर विचार–विमर्श एवं वाद–विवाद 70 के दशक से प्रारंभ हो गया था। भारत में पर्यावरण का जन आंदोलन 1972 से स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद से व्यवहारिक रूप से सामने आया। स्टॉकहोम सम्मेलन के तत्कलीन प्रभाव से' नेशनल कमेटी फॉर एनवायरनमेंट प्लानिंग एण्ड कॉ–ऑर्डिनेशन (National Committee for Environment Planning and Co & Ordination :NCEPC) की स्थापना की गई। कमेटी का अध्ययन पर्यावरणीय राष्टोय नीति ' बनाने का आधार तैयार किया। 1980 के चुनावों में लगभग सभी राजनीतिक पाटियों ने ''पर्यावरण सुरक्षा 'को अपने चुनावी मुद्वों में 'शामिल किया था।[7] वर्ष 1972 में वायु तथा जल प्रदूषन को रोकने के उद्देशय से केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर 'प्रदूषण नियंत्रण मंडल ' (Pollution Control Bord)बनायें गये।

1980 में तात्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तिवारी कमेटी बनाई, जिसकी अभिशंसा पर पर्यावरणीय कार्यकम के नियोजन ,प्रोत्साहन तथा समन्वय के लिए उसी वर्ष नवम्बर में 'स्वतंत्र पर्यावरण विभाग' की स्थापना की गई। पहले वन मंत्रालय में केवल वन तथा वन्य जीव विभाग था। बाद में राष्ट्रपति की विज्ञप्ति संख्या 74। 02। 85 दिनांक 04। 01। 1985 द्वरा पर्यावाण विभाग को वन मंत्रालय का हिस्सा बनाया गया। वन मंत्रालय को पर्यावरण तथा वन मंत्रालय नाम दिया गया। वन तथा वन्य जीव विभाग में 'राष्ट्रीय भूमि विकास बोई और केन्द्रीय गया प्राधिकरण जैसे अनुभाग भी स्थापित किए गए।ख्8, 1980 के दशक के बाद इसके कार्यों और उत्तरदायित्वो में शनैः शनैः वृद्वि होती गई। पर्यावरण से संस्थानों,अभिकरणों की स्थापना ,कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के विस्तारीकरण से देश की पर्यावरण के प्रति सजगता आर प्रतिबद्वता परिलक्षित होती है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और वनस्पति उद्यान, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, पारिस्थितिकी विकास बोर्ड, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद आदि संस्थानों की स्थापना पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक सोच को दर्शाता है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 12, December 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

निष्कर्षतः कहा जा सकता है, कि पर्यावरण से संबंधित मुद्दें वैश्विक त्रासदी बन गया है। वैश्विक पर्यावरणिक प्रभाव से विश्व का कोई देश अछूता नहीं रहा है विश्व के कई देशों में कई छोटी –बड़ी दुर्दान्त और दुखान्त पर्यावरणिक घटनाएँ घटी है। भावी विनाश से बचने के लिए पर्यावरण संरक्षण हेतु स्टॉकहोम, हैलिंसकी, लंदन, वियाना, मांट्रियल आदि स्थानों पर प्रमुख पर्यावरण सम्मेलनों का आयेजन किया गया, जिसमें राष्ट्रों को दिशा निर्देशित करने वाली पर्यावरण संरक्षण की नैदानिक नीतियाँ तय की गई। साथ ही साथ सकारात्मक भूमिका निर्वहन करने वाले अन्तराष्ट्रीय संगठनों की स्थापना की गई। सभी देशों के बीच रणनीतिक भेद एवं प्राथमिकताओं में भिन्नता रहीं, फिर भी पर्यावरण संरक्षण का पयास मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस संदर्भ में कई चुनौतियों का सामना करते हुए विकासोन्मुख भारत के सफल प्रयासों को नकारा नही जा सकता है।

संदर्भ सूचीः–

1. फ्रासिंस हैरिस, ग्लोबल एनवायरमैण्टल ईशूज, जॉन विलीएंडसंस, पृ0–04
2. हेविडश्डी कें एक्सल्योरिंग एनवायरमेण्टल इशूज, वर्ष– 2009, पृ0–15
3. डॉ0 एस0 के0 गायलः पर्यावरण शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा, प्रकाशन वर्ष–2014, पृष्ट संख्या– 284–85
4. संयुक्त राष्ट्र संधः मानव पर्यावरण, सम्मेलन, स्टाकहोम (स्वीडेन) प्रकाशन वर्ष– 5–16 जून, 1972
5. (तपन विशाल अन्तराष्ट्रीय संबंध, वित्तीय संस्करण, ओरियोंट स्लैकस्वॉल, हैदराबाद, 2016, पृ0–453)
6. नरौबी घोषणा–पत्र (कैन्या) 10–18 जून, 1982
7. रियो सम्मेलन, ब्राजिल, प्रकाश वर्ष–3–14 जून 1992
8. निकोसन, माइकल, इन्टनेशनल रिलेशन एक कॉन्फ्रेन्स इंट्रोडक्सशन, न्यूयार्क, पृ0ः 219।
9. जॉन बेर्यालय एड स्मिथ, द ग्लोबलाईजेशन आफ वर्ल्ड पॉलिरकस ऑक्सफॉर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ0–452
10. वार्षिक रिपोर्ट, वर्ष–2003–04 से 2005–06, वन एंव पर्यावरण मंत्रालय सरकार।
11. द हिन्दू 4 सितम्बर 2009